बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 101 ● नई दिल्ली ● वीरवार 29 जनवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

मनरेगा की बहाली के लिए लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करेगा विपक्ष : कांग्रेस

नई दिल्ली । कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि विपक्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की बहाली की मांग के लिए सभी लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करेगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के दौरान, सभी विपक्षी दलों ने मनरेगा को बुलडोजर से (संख्या बल के आधार पर बिना आम सहमति बनाये) खत्म किए जाने के खिलाफ पूरे सम्मान और गरिमापूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराया। रमेश ने 'एक्सपर पोस्ट किया, ''आज संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान, सभी विपक्षी दलों ने मनरेगा को बुलडोजर से खत्म किए जाने के खिलाफ पूरे सम्मान और गरिमापूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराया।

जनसेवा, सिद्धांत और संघर्ष की अमिट विरासत– राम बाबू शर्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि

500 से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य व नेत्र जाँच का लाभ, राम बाबू शर्मा दूरदर्शी, कर्मठ और जनप्रिय नेता थे — जयप्रकाश अग्रवाल

नई दिल्ली। (इंद्रजीत सिंह)दिल्ली की राजनीति और जनसेवा में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले पूर्व विधायक एवं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय राम बाबू शर्मा की 17वीं पुण्यतिथि पर कबूल नगर, शाहदरा स्थित श्री साई मंदिर में श्रद्धांजलि सभा एवं निःशुल्क स्वास्थ्य व नेत्र जाँच शिविर का आयोजन किया गया। श्रद्धा, सम्मान और सेवा भाव से ओत-प्रोत इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने स्वर्गीय राम बाबू शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सेवा शिविर के दौरान 500 से अधिक जरूरतमंदों की जाँच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयाँ एवं चश्मे वितरित किए गए, जिससे जनसेवा के प्रति राम बाबू शर्मा की सोच साकार रूप में दिखाई दी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल,

स्वर्गीय राम बाबू शर्मा के सुपुत्र एवं पूर्व विधायक विपिन शर्मा, समाजसेवी पारस शर्मा (पिंकी), पूर्व विधायक एवं यमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, पार्षद शिवानी पांचाल, पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, जुबैर अहमद, भीष्म शर्मा, ईश्वर बागड़ी, अश्वनी शर्मा, सुशील तिवारी, महेश कपूर, मयंक चतुर्वेदी, जय करण चौधरी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर जयप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि स्वर्गीय राम बाबू शर्मा एक दूरदर्शी, कर्मठ, सिद्धांतनिष्ठ और जनप्रिय नेता थे, जिनका संपूर्ण जीवन जनसेवा और संगठन निर्माण को समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस दल के नेता के रूप में उनके कार्य आज भी प्रेरणास्रोत हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि राजीव भवन का निर्माण स्वर्गीय राम बाबू शर्मा का ऐतिहासिक योगदान है, जो आज भी कांग्रेस संगठन की वैचारिक शक्ति और लोकतांत्रिक संघर्षों का केंद्र बना हुआ है। पूर्व विधायक अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि राम बाबू शर्मा का जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि राजनीति सत्ता की नहीं, बल्कि समाज और लोकतंत्र की सेवा का माध्यम होनी चाहिए। एक्रिडेटेड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय शंकर चतुर्वेदी ने कहा कि एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय राम बाबू शर्मा को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके आदर्शों को नमन किया गया। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की विशाल उपस्थिति और सेवा गतिविधियों ने यह सिद्ध कर दिया कि स्वर्गीय राम बाबू शर्मा आज भी जन-जन के दिलों में जीवित हैं।

धर्म-परिवर्तन कर अल्पसंख्यक आरक्षण मांग रहे उम्मीदवारों की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह नए किस्म का फ्रॉड

नई दिल्ली ।

खुद को बौद्ध बता कर मेडिकल पीजी में अल्पसंख्यक आरक्षण मांग रहे 2 उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने इसे नए किस्म की धोखाधड़ी कहा. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह टिप्पणी तब की जब उसे जानकारी मिली कि लिखित परीक्षा से पहले इन उम्मीदवारों ने खुद को सामान्य वर्ग का बताया था और दोनों हरियाणा की समृद्ध जाट जाति से हैं. कोर्ट ने हरियाणा सरकार से भी इस मामले में कड़े सवाल किए हैं. मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज को बौद्ध अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षण दिया जाता है. निखिल कुमार पुनिया और एकता ने सुभारती मेडिकल कॉलेज में नीट पीजी कोर्स में अपने लिए सीट की मांग की है. उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का दावा करते हुए एसडीओ (सब डिविजनल ऑफिसर) कार्यालय से जारी प्रमाण पत्र भी पेश किया था. खुद भी हरियाणा से आने वाले चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, पुनिया उपनाम जाट भी लिखते हैं और अनुसूचित जाति के लोग भी. आप कौन से पुनिया हैं? वकील ने जवाब दिया कि उनके मुवक्किल जाट हैं. इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि वह अल्पसंख्यक कैसे हो गए?

वकील ने कहा कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है. यह उनका संवैधानिक अधिकार है. वकील की बात पर सीजेआई ने टिप्पणी की, वाह! यह तो धोखाधड़ी का एक नया तरीका है. आप वास्तविक अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनना चाहते हैं.

आप सबसे समृद्ध, सुविधासंपन्न और उच्च जाति समुदायों में से एक से हैं. इस समुदाय के पास कृषि भूमि है. सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं. आपको उन लोगों के अधिकार नहीं छीनने चाहिए, जो वास्तव में वंचित हैं. याचिकाकर्ता के वकील ने बचाव करते हुए कहा, हमने वास्तव में और ईमानदारी से बौद्ध धर्म अपनाया है. इस पर चीफ जस्टिस ने चेतावनी देते हुए कहा, हमें आगे और टिप्पणी करने के लिए मजबूर मत कीजिए. इस तरह की दलील को मंजूरी दी गई तो सभी लोग यही शुरू कर देंगे. उच्च जातियां धर्म परिवर्तन करने लगेंगी और वास्तविक हकदारों के अधिकार का हनन होगा. बेंच के सदस्य जस्टिस जोयमाल्या बागची ने भी याचिकाकर्ता की दलील पर कड़ा एतराज जताया. इसके बाद कोर्ट ने अल्पसंख्यक उम्मीदवार के रूप में प्रवेश की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं का आवेदन खारिज कर दिया. इसके बाद कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूरे घटनाक्रम पर जवाब मांग लिया. कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार राय में अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने से जुड़े दिशा-निर्देशों की जानकारी दे. सरकार यह साफ करे कि क्या उच्च जाति के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार, बौद्ध धर्म अपनाने का दावा कर, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं? कोर्ट ने राय सरकार से 2 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

द्वारका कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल से मचा हड़कंप; पुलिस कर रही जांच

नई दिल्ली ।

राजधानी दिल्ली के द्वारका कोर्ट में आज सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जब कोर्ट परिसर में बम रखे होने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है। इस सूचना के मिलते ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया।

बम की धमकी मिलने की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं। साइबर सेल धमकी भरे मेल की जांच कर रही है। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड को बुलाया गया है। अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। साइबर सिटी में 13 निजी स्कूलों में बुधवार की सुबह बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ईमेल मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टी कर दी और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही संबंधित स्कूलों में पुलिस की टीमों ने पहुंचकर सर्च अभियान शुरू कर दिया। स्कूलों में बुधवार सुबह धमकी भरा ईमेल उस समय मिला, जब बच्चे स्कूल पहुंच रहे थे या पहुंच चुके थे। धमकी भरी ईमेल स्कूलों को अलग-अलग समय में मिली हैं।

सूचना मिलते ही पुलिस की टीमों के साथ ही बम स्क्वायड, डॉग स्क्वायड और एसडीआरएफ की टीमों ने संबंधित स्कूलों में पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। जांच टीमों ने स्कूल परिसरों के साथ-साथ आसपास के संवेदनशील इलाकों में भी सघन तलाशी अभियान चलाया। स्कूलों के कमरों, शौचालयों, मैदानों, गमलों से लेकर हर संभावित स्थान की बारीकी से जांच की गई।

पुलिस व अन्य टीमों को जांच में किसी भी स्कूल से कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। फिलहाल पुलिस उस ईमेल भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करने और धमकी के पीछे की सच्चाई जानने के लिए तकनीकी जांच में जुटी है।

बजट सत्र के दौरान भी उठेगा मनरेगा और एसआईआर का मुद्दा, विपक्ष ने तय की विरोध की रणनीति

नई दिल्ली । संसद में बजट सत्र आज से शुरू है। इस दौरान विपक्षी दलों ने सत्र में नए मनरेगा कानून और एसआईआर के मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का निर्णय लिया। सूत्रों ने बताया कि कई विपक्षी दलों के नेताओं ने यहां राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के कक्ष में मुलाकात की। इसके साथ ही बजट सत्र के लिए विपक्ष की रणनीति पर चर्चा की।

नेताओं ने धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान और साथ ही केंद्रीय बजट की प्रस्तुति और उस पर बहस के दौरान भी विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। एआईसीसी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ÷विपक्ष मनरेगा की बहाली की मांग के लिए सभी लोकतांत्रिक साधनों का इस्तेमाल करेगा।लोकसभा और रायसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि यह शर्म की बात है। उन्होंने कहा, आज विपक्ष का जो रवैया रहा, वह देश के लिए शर्म की बात है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। जब वंदे मातरम की 150वीं जयंती पर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तब विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और कार्यवाही बाधित की, जबकि देश को उनके बलिदानों को याद करना चाहिए था।बैठक के दौरान टीएमसी और आप के नेता उपस्थित नहीं थे, जिसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, एआईसीसी महासचिव रमेश और केसी वेणुगोपाल, डीएमके के टीआर बालू, शिवसेना (यूबीटी) के अरविंद सावंत, समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, आरजेडी के प्रेम चंद गुप्ता, सीपीआई (एम) के जॉन ब्रिटास, सीपीआई के पी संदोष और आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन सहित अन्य लोग शामिल थे। विपक्ष की यह बैठक कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा संसद के बजट सत्र में मनरेगा और एसआईआर से संबंधित मुद्दों को उठाने के निर्णय के एक दिन बाद हुई है। वहीं, सरकार ने इन मुद्दों पर दोबारा बहस करने से इनकार कर दिया था। यह निर्णय मंगलवार को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर आयोजित पार्टी के संसदीय रणनीति समूह की बैठक में लिया गया, जिसमें लोकसभा और रायसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और खर्गे भी उपस्थित थे।

अजित पवार को राहुल गांधी की श्रद्धांजलि, बोले- ईमानदार नेता खो दिया, खर्गे ने भी जताया दुख

नई दिल्ली। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया, जिनका आज सुबह विमान दुर्घटना में निधन हो गया। पवार के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खर्गे ने कहा कि उन्हें एक अनुभवी राजनीतिज्ञ के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने ईमानदारी और सूझबूझ से काम किया। खरगे ने एक्स पर लिखा कि विमान दुर्घटना में अजीत पवार के दुखद निधन की खबर बेहद चौंकाने वाली और बेहद दुखद है। यह एक ऐसे नेता का असामयिक देहांत है जिनका राजनीतिक करियर लंबा और उज्ज्वल था। इस कठिन घड़ी में शोक संतप्त परिवार जिस अपार दुःख से गुजर रहा है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा कि मैं पूरे पवार परिवार, उनके समर्थकों और शुभचिंतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। महाराष्ट्र की जनता की विभिन्न संवैधानिक पदों पर सेवा करने वाले

अजीत पवार को एक अनुभवी राजनीतिज्ञ के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने अपनी जनता के प्रति अपने दायित्वों को ईमानदारी और सूझबूझ से निभाया। उनकी आत्मा को शांति मिले। राहुल गांधी ने आज सुबह मुंबई से बारामती जा रहे चार्टर्ड विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर अजीत पवार और चार अन्य लोगों के निधन पर शोक व्यक्त किया। लोकसभा सांसद ने लिखा कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार जी और उनके सहयात्रियों के आज विमान दुर्घटना में निधन की खबर अत्यंत दुखद है। इस दुःख की घड़ी में मैं महाराष्ट्र की जनता के साथ खड़ा हूँ। इस दुख की घड़ी में मैं पूरे पवार परिवार और उनके प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। इससे पहले आज, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कह कि मैं पूरे पवार परिवार और उनके समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। मैंने अजीत पवार की पत्नी और सुप्रिया जी (सुप्रिया सुले) से बात की है। महाराष्ट्र कांग्रेस सांसद प्रणिति शिंदे ने इस खबर पर गहरा सदमा व्यक्त किया। उन्होंने कहा, यह खबर सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा। वे समय के पाबंद थे। उनकी व्यस्त जीवनशैली ने आज उनकी जान ले ली। वे हमेशा अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते थे।

हिन्दू-मुस्लिम सद्भाव के लिए संवाद जरूरी

साझा विरासत और गंगा जमुनी परंपरा का देश है भारत, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध आदि सभी धर्मों के अनुयायियों की शताब्दियों से धर्म स्थली और कर्म स्थली है भारत, जहां हिंदू-मुस्लिम ऐसे ही घुल-मिल कर रहते चले आए है, जैसे दूध में शक्कर और इस प्रकार से एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, जैसे नाखून से गोश्त। सदियों से एक ही समाज में हिंदू अपने आराध्यों की उपासना और मुस्लिम अपनी इबादतें करते चले आए हैं। शुरू में हिंदू-मुस्लिम समस्या थी ही नहीं। यह तो अंग्रेजों ने अपना उल्लू साधने और गांठने के लिए इन संप्रदायों के बीच अविश्वास और दुश्मनी का बीज डाला, वरना सर सैयद अहमद खां, संस्थापक, एएमयू तो हिंदुओं और मुसलमानों को हिंदुस्तान नामी दुल्हन की दो खूबसूरत आंखें कहा करते थे। यह आज भी ऐसे ही हैं, मगर वोट बैंक की सियासत ने इस आपसी स्नेह और भाईचारे को खंडित कर दिया, स्वाहा कर दिया। हमें यह भी समझना होगा कि किन लोगों के कारण ऐसा हुआ है। वास्तव में ये वे लोग हैं, जिन पर जनता इस बात का विश्वास करके सत्ता के गलियारों में स्थान देती है कि सिस्टम चलाने में वे उनकी सेवा करेंगे। जब वे लोग जीत कर किसी भी गद्दी पर विराजमान होते हैं तो केवल चंद लोग जिनकी संख्या ऐसे ही होती है, जैसे आटे में नमक या ऊंट के मुह में राई, सभी जनता की सेवा करने के अपनी निजी सेवा में व्यस्त हो जाते हैं, जिसके कारण भारत विश्व गुरु नहीं बन पा रहा है। ऐसे लोग पक्ष-विपक्ष, सभी दलों में होते हैं। भारत का इतिहास गौरव और पीड़ा–दोनों का साक्षी है। लेकिन इतिहास का उपयोग वर्तमान को जहरीला बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। बीते युगों की गलतियों का बोझ आज की पीढ़ियों पर लादना न तो न्यायसंगत है, न ही व्यावहारिक। सद्भाव का तक़ाज़ा है कि हम इतिहास से सीख लें, पर उसमें कैद न रहें। भारत केवल एक राष्ट्र नहीं, बल्कि अनेक आस्थाओं, परम्पराओं और विश्वासों का साझा घर है। यहां मंदिर की घंटियों, मस्जिद की अज़ान, गुरुद्वारे के कीर्तन और, बौद्ध मठों की पूजा, चर्च की प्रार्थनाएं–सदियों से एक-दूसरे के साथ गूंजती रही हैं। यही सह-अस्तित्व भारत की आत्मा है। परन्तु विडम्बना यह है कि आज इसी विविधता को विभाजन का कारण बनाया जा रहा है। ऐसे समय में अन्तर्धर्म सद्भाव और संवाद केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि सामाजिक अस्तित्व की अनिवार्यता बन चुका है। संवाद का अर्थ केवल अपनी बात मनवाना नहीं, बल्कि दूसरे को भी धैर्य से सुनना है। सद्भाव का अर्थ- सहमति नहीं, सम्मान है। अन्तर्धर्म सद्भाव का अर्थ यह नहीं कि सभी एक-दूसरे के धार्मिक विश्वासों से सहमत हों। इसका मूल भाव है, असहमति के बावजूद सम्मान। प्रत्येक धर्म अपने अनुयायियों को नैतिकता, करुणा और सत्य का पाठ पढ़ाता है। जब धर्म नफ़रत का माध्यम बनता है, तब वह अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है। यह घोर अन्याय होगा, यदि संघ व हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य सद्भावना की बयार चलने वाली इंटर फेथ हार्मनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया का ज़िक्र न हो, जो 2005 से यह काम कर रही है, और जिसके अध्यक्ष ख़्वाजा इफ़्तिखार अहमद को शाबाशी न दी जाए, जिसके परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। संगठन मानता है कि जहां संवाद समाप्त होता है, वहीं से टकराव शुरू होता है। दुर्भाग्य से, आज सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानबाज़ी ने संवाद की जगह आरोप-प्रत्यारोप को बढ़ावा दिया है। अन्तर्धर्म संवाद का अर्थ है। सुनने की इच्छा, समझने का धैर्य और अपनी धारणाओं की ईमानदार समीक्षा। संवाद डर को कम करता है, भ्रांतियों को तोड़ता है और विश्वास की नींव रखता है। जनता को दोनों ओर से ऐसे स्वयंभू नेताओं और हमदर्दों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और परहेज़ करना चाहिए, जो अपनी क़ौम की वकालत इस प्रकार से कार्य हैं, कि उसका सुप्रभाव के बजाय कुप्रभाव पड़ता है, संवाद केवल भाषणों से नहीं आता। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में संवैधानिक मूल्य, आलोचनात्मक सोच और बहुलतावाद को मजबूत करना होगा। नागरिक के रूप में हमारी पहचान धार्मिक पहचान से ऊपर हो, यही लोकतंत्र की बुनियाद है। आज संघ के सरसंघ चालक, डॉ. मोहन भागवत और उसके वरिष्ठ वरिष्ठ नेताओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी व उनकी टीम के महत्वपूर्ण सदस्य, जैसे अमित शाह और अजीत डोभाल साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प हैं। प्रायः देखा गया है कि किसी भी आतंकवादी घटना के बाद मुस्लिम डरे, सहमे से हो जाते हैं कि कहीं उनसे देशभक्त होने का प्रमाण पत्र नहीं मांग लिया जाए। हिंदू-मुस्लिम सांप्रदायिक समस्या आज की नहीं, सैकड़ों साल पुरानी है और इन संवादों से एक दिन में नहीं जाएगी, मगर एक दिन अवश्य जाएगी, अगर दोनों ओर सच्चाई और ईमानदारी से विचार और उसके बाद के आचार से इसका निदान हो सकता है।आज समझौते से अधिक, समझ की बात करने की आवश्यकता है, ठीक ऐसे ही, जैसे, ध्रुवीकरण नहीं, संवाद को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से धर्म नहीं, मानवता को केंद्र में रखते हुए संवाद किया जा रहा है। आज हमें महात्मा गांधी, केशव बलिराम हेडगेवार और मौलाना आज़ाद की एक साथ जरूरत है, ताकि डेढ़ सौ करोड़ के पूर्ण समाज को एकजुट रखा जा सके। अन्तर्धर्म संवाद और सद्भाव कोई तात्कालिक नारा नहीं, बल्कि निरन्तर अभ्यास है, संवाद का, संयम का और सह-अस्तित्व का। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने-अपने विश्वासों पर गर्व करते हुए भी दूसरे के विश्वास का सम्मान करना सीखें। क्योंकि जब धर्म मानवता से जुड़ता है, तब समाज मजबूत होता है और जब मानवता छूट जाती है, तब धर्म भी खोखला हो जाता है।

समझौते की चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स

2007 में यानि 18 साल से भारत और यूरोपीय संघ में चली आ रही मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता अंततः सम्पन्न हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां एक ओर दुनिया भर के देशों को टैरिफ की जो धमकियां देते हुए डराने में लगे हुए हैं तो वहीं भारत लगातार इन धमकियों को धुआं-धुआं उड़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच एफटीए समझौते की घोषणा करते हुए कहा कि दुनिया के लोग इस समझौते की चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। यह समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है। यूरोपीय संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने देशवासियों को इसकी जानकारी दी। यूरोपीय उद्योग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कोस्टा ने सोमवार को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर भारत की सैन्य शक्ति, शौर्य और सांस्कृतिक विविधता को देखा। इन दोनों का गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना भारत और यूरोपीय संघ के मजबूत हो रहे रिश्तों को प्रदर्शित करता है। यह डील केवल व्यापार के महत्व को ही नहीं दिखाती बल्कि यह प्रदर्शित करती है कि वैश्विक कूटनीति में भारत की स्थिति कितनी मजबूत है और भारत पावर प्ले में शामिल हो चुका है। भारत ने अमेरिका का गुलाम बनना स्वीकार नहीं किया। ट्रंप नई दिल्ली को अपमानित कर व्यापार समझौता करना चाहते थे और वह भी अपनी शर्तों पर। प्रधानमंत्री मोदी को यह स्वीकार्य न था। उनकी राष्ट्रवादी नीतियां भी इसकी अनुमति नहीं देती थीं। इसलिए भारत अमेरिका व्यापार वार्ता किसी तार्किक निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। भारतीय हितों के साथ किसी भी तरह का समझौता देशवासियों को भी स्वीकार्य नहीं होगा। जिस तरह से ट्रंप ने डेनमार्क के ग्रीनलैंड को लेकर धमकियां दीं उससे स्थिति पूरी तरह से बदल गई। यूरोप चारों तरफ से मुश्किलों में घिरा है। रूस की आक्रामकता, चीन का दबाव और अपनी कई कमजोरियां। ऊपर से अमेरिका की ओर से छोड़े जाने की चिंताएं अब वाशिंगटन के डराने-धमकाने के डर में बदल गई है। इसके उलट भारत स्थिरता का प्रतीक है। यह एक ऐसा बाजार प्रदान करता है जो लगातार बढ़ रहा है। भारत कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं करता। हो सकता है कि नई दिल्ली जलवायु या यूक्रेन जैसे मुद्दों पर यूरोप की राजधानियों से पूरी तरह सहमत न हो। लेकिन, कम से कम वह उन्हें धमकाने, उनकी संपत्ति छीनने या अपमानित करने की कोशिश नहीं करता। ट्रंप के टैरिफ का मुकाबला करने के लिए भारत को एक के बाद एक व्यापार समझौते करना आदर्श तरीका लगा। यूरोप के साथ डील करना समय की मांग थी। ट्रंप को भी यह सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा कि भारत के पास अब कई विकल्प मौजूद हैं। भारत जानता है कि इस डील से ट्रंप को मिर्ची लगेगी, अमेरिका ने चेतावनी दी है कि भारत के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर करके यूरोप ने अपने ही खिलाफ रूसी जंग को फंडिंग दे रहा है। न तो भारत ने और न ही यूरोप ने अमेरिका की प्रतिक्रिया को गंभीरता से लिया है। अगर मदर ऑफ ऑल डील्स की प्रकृति की बात करें तो इससे दोनों पक्षों को बड़ा फायदा होगा। वित्त वर्ष 2025 में भारत यूरोपीय संघ का व्यापार 136 अरब डालर से अधिक हो चुका है। जिसमें भारत का निर्यात 76 अरब डालर और आयात लगभग 60 अरब डालर रहा है।

इस तरह यूरोपीय संघ व्यापार में भारत का सबसे बड़ा साझेदार बना हुआ है। इस डील से 90 प्रतिशत से ज्यादा सामानों पर टैरिफ कम किया जा सकता है या इसे हटाया जा सकता है। इससे खासतौर पर कपड़े, फार्मा, इंजीनियरिंग प्रोडक्टस और आईटी सर्विसेज समेत कई सैक्टरों को बड़ा लाभ होगा। इस डील से भारत के लिए यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों वाले बाजार तक अधिक पहुंच बनेगी। ईयू में करीब 45 करोड़ उपभोक्ता हैं और डील से भारतीय कंपनियों को सीधे यूरोपीय बाजार में एंट्री आसान होगी। ईयू भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर है और एफटीए से 90 प्रतिशत से ज्यादा सामान पर टैक्स हटने से भारत का निर्यात बढ़ेगा। निवेश (एफडीआई) में उछाल आएगा, यूरोपीय कंपनियां भारत में तमाम सैक्टर्स में अपना निवेश बढ़ा सकती हैं। निर्यात-निवेश बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं सप्लाई चेन में सुधार से चीन पर निर्भरता में भी कमी आएगी। दोनों पक्ष एक रक्षा ढांचा समझौता और रणनीतिक एजेंडे पर भी आगे बढ़ेंगे। इससे यूरोपीय कम्पनियों के लिए भारत का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। भारतीय कम्पनियों को यूरोपीय संघ के सुरक्षित कार्यक्रम में भागीदारी का अवसर मिलेगा जो 150 अरब यूरो का रक्षा वित्तीय तंत्र है। यूरोप के लिए भी इलैक्ट्रोनिक्स उत्पाद, मशीनरी उपकरण, विमानों के पुर्जे, दवाइयां, वाहन आदि उत्पादों के लिए भारत का बाजार मिलेगा। रणनीतिक रूप से यूरोपीय संघ अपनी सप्लाई चेन को विविध करना चाहता है ताकि वह चीन पर अपनी अत्याधिक निर्भरता को कम कर सके। यूरोपीय संघ भारत के यात्री वाहन बाजार में बेहतर पहुंच चाहता है। जहां वर्तमान में आयात शुल्क 100 से 125 प्रतिशत लगाया जाता है। एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता ईयू के साथ भारत की व्यापारिक स्थिति को काफी मजबूत कर सकता है।

इस समझौते से वित्त वर्ष 2031 तक यूरोपीय संघ के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस 50 अरब डॉलर से अधिक बढ़ सकता है। इससे भारत के कुल निर्यात में ईयू संघ की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2025 के 17.3 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर लगभग 22-23 प्रतिशत हो सकती है, जिससे भारत की निर्यात वृद्धि को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। ट्रंप ने अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए जिस तरह से टैरिफगिरी दिखाई उसका जवाब तो उन्हें मिल गया है। इस वर्ष भारत की नजर अहम आर्थिक और वैश्विक घटनाओं पर टिकी रहेगी। भारत को वित्तीय बाजार के घटनाक्रम पर नजर रखनी होगी और साथ ही मुक्त व्यापार समझौतों को जमीनी स्तर पर कारगर बनाने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे और घरेलू बाजार की प्रतिक्रिया का आकलन भी करना होगा। फिलहाल दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का मिलन हो गया है।

सम्पादकीय...

यूजीसी की नई गाइडलाइनः सवर्ण छात्रों को संदेह के कटघरे में खड़ा करती व्यवस्था

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा हाल ही में जारी की गई नई गाइडलाइन ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और सुरक्षा के नाम पर एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया है, जिसने सवर्ण वर्ग के छात्रों को असहज, आशंकित और असुरक्षित बना दिया है। विशेष रूप से वह प्रावधान, जिसमें ओबीसी, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं दिव्यांग वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव, मारपीट या जाति आधारित व्यवहार के मामलों में सवर्ण छात्र को सीधे दोषी की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाता है, गंभीर प्रश्न खड़े करता है। यूजीसी की नई गाइडलाइन के अनुसार यदि किसी सवर्ण छात्र पर यह आरोप लगता है कि उसने किसी ओबीसी, अनुसूचित जाति या दिव्यांग छात्र के साथ भेदभाव किया है, तो संस्थान स्तर पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। समस्या यह नहीं कि भेदभाव के विरुद्ध सख्ती की जा रही है, समस्या यह है कि यहाँ जांच से पहले ही मानसिक रूप से दोषी मान लेने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यह न्याय के उस मूल सिद्धांत के विपरीत है, जिसमें दोष सिद्ध होने तक व्यक्ति निर्दोष माना जाता है। आज का सवर्ण छात्र यह महसूस कर रहा है कि वह किसी भी शैक्षणिक परिसर में कदम रखते ही संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। एक छोटी-सी बहस, सामान्य विवाद या व्यक्तिगत टकराव भी यदि जाति के चश्मे से देखा गया, तो उसका परिणाम सवर्ण छात्र के लिए निलंबन, एफआईआर या शैक्षणिक भविष्य पर संकट के रूप में सामने आ सकता है। यह स्थिति न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि भय का वातावरण भी बनाती है। यूजीसी की गाइडलाइन में यह स्पष्ट असंतुलन दिखाई देता है कि एक वर्ग को संरक्षण देने के नाम पर दूसरे वर्ग को कठोर निगरानी और दंड के दायरे में डाल दिया गया है। यदि वास्तव में उद्देश्य न्याय है, तो नियम सभी के लिए समान होने चाहिए। केवल सामाजिक पहचान के आधार पर किसी छात्र को संभावित अपराधी मान लेना शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता पर गंभीर आघात है। शैक्षणिक संस्थान संवाद, विचार और सह-अस्तित्व के केंद्र होते हैं, न कि डर और संदेह के। नई गाइडलाइन के बाद सवर्ण छात्रों में यह डर गहराता जा रहा है कि कहीं कोई असत्य या अतिरंजित आरोप उनके पूरे भविष्य को नष्ट न कर दे। यह स्थिति शिक्षा के मूल उद्देश्य–ज्ञान, समरसता और राष्ट्र निर्माण–को कमजोर करती है। सवर्ण वर्ग का विरोध किसी भी वंचित या आरक्षित वर्ग के अधिकारों के खिलाफ नहीं है। यह विरोध एकतरफा और असंतुलित नीति के खिलाफ है, जहाँ दंड की तलवार केवल एक वर्ग के सिर पर लटकती दिखाई देती है। यदि भेदभाव होता है, तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन निष्पक्ष जांच और समान न्याय के साथ। यूजीसी को नई गाइडलाइन में तत्काल पुनर्विचार की आवश्यकता है। शिक्षा व्यवस्था को सामाजिक न्याय का माध्यम बनाते हुए भी न्यायपूर्ण बनाए रखना अनिवार्य है। किसी भी वर्ग–चाहे वह सवर्ण हो या वंचित–को बिना निष्पक्ष प्रक्रिया के दोषी ठहराना लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है। सवर्ण छात्रों की आशंकाएं वास्तविक हैं, और उन्हें अनदेखा करना भविष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है।

सरल नहीं पर प्रभावशाली थे, आदर्शवादी नहीं पर निर्णायक थे अजित पवार

महाराष्ट्र की राजनीति को आज तब गहरा आघात लगा जब उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बारामती में विमान हादसे में निधन हो गया। लैंडिंग के दौरान विमान में आई तकनीकी खराबी के बाद यह दुर्घटना हुई। हादसे की खबर फैलते ही राज्य भर में शोक की लहर दौड़ गई। देखा जाये तो अजित पवार महाराष्ट्र के उन नेताओं में थे जिन्होंने सत्ता के केंद्र में रहते हुए भी जमीन से नाता नहीं तोड़ा। वह भले ही कभी मुख्यमंत्री न बने हों, लेकिन राज्य में सबसे लंबे समय तक उपमुख्यमंत्री रहने का इतिहास उनके नाम दर्ज है। छह बार उपमुख्यमंत्री के रूप में सेवा देने वाले अजित पवार ने अलग-अलग सरकारों में अपनी प्रशासनिक पकड़ और राजनीतिक प्रभाव बनाए रखा। बारामती में अजित पवार की राजनीति का सबसे बड़ा प्रमाण उनका काम खुद था। वह उन गिने चुने नेताओं में थे जिनके लिए अपना खुद का चुनाव प्रचार एक औपचारिकता भर था। विधानसभा चुनावों में वह हमेशा समय पर अपना नामांकन दाखिल करते थे, लेकिन उसके बाद बारामती की गलियों में शायद ही कभी उन्हें प्रचार करते देखा गया। जनता जानती थी कि किसे वोट देना है, इसलिए जनता ही उनका प्रचार करती थी। अजित पवार का भरोसा नारों पर नहीं, काम पर था। इसी आत्मविश्वास के चलते वह बारामती से निश्चिंत रहकर राज्य के दूसरे इलाकों में पार्टी उम्मीदवारों के प्रचार में जुट जाते थे। बारामती उनके लिए सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं था, वह उनका कर्मक्षेत्र था, जहां उन्होंने यह साबित किया कि जब विकास बोलता है तो नेता को खुद बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अजित पवार ने 1982 में सहकारी क्षेत्र से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। वह चीनी मिल के बोर्ड में चुने गए और यहीं से बारामती की राजनीति में उनकी जड़ें मजबूत होती गईं। 1991 में वह पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने और उसी वर्ष बारामती से लोकसभा सांसद चुने गए। बाद में उन्होंने यह सीट शरद पवार के लिए खाली की। इसके बाद वह बारामती से सात बार विधायक बने। उनके परिवार में पत्नी सुनेत्रा पवार और दो पुत्र जय

और पार्थ हैं। सहकार से सत्ता तक का उनका सफर बारामती से शुरू हुआ और वहीं समाप्त हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को चुनाव आयोग ने पार्टी का मूल नाम और चुनाव चिन्ह सौंपा था। यह गुट भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति के साथ जुड़ा। वहीं उनके चाचा और वरिष्ठ नेता शरद पवार ने अलग रह कर एनसीपी-एससीपी का नेतृत्व संभाला। वह विभाजन महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे भावनात्मक और निर्णायक मोड़ माना गया। दोनों पक्षों का विवाद अदालत के दरवाजे तक पहुँचा लेकिन हाल के दिनों में पवार परिवार एकजुट नजर आ रहा था। हम आपको याद दिला दें कि 2024 के लोकसभा चुनावों में अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ उतार कर पारिवारिक और राजनीतिक रिश्तों में खोखापन ला दिया था, लेकिन समय के साथ उन्होंने यह स्वीकार किया था कि वह फैसला एक भूल था। राजनीति के उस कठोर दौर के बाद हालिया निकाय चुनावों में उन्होंने जिस परिपक्वता का परिचय दिया, वह उनके व्यक्तित्व का दूसरा और अधिक मानवीय पक्ष सामने लाता है। शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन कर दोनों एनसीपी को एक मंच पर लाने की पहल उन्होंने खुद की थी। बहन सुप्रिया के साथ संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने साफ कहा था कि परिवार में कोई मतभेद नहीं है और जनता चाहती है कि दोनों दल साथ मिलकर काम करें। यह सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक स्वीकारोक्ति भी थी। देखा जाये तो अपने निधन से पहले अजित पवार कम से कम इतना तो कर ही गए कि उन्होंने परिवार से सुलह कर ली, टूटे रिश्तों को जोड़ दिया और महाराष्ट्र की राजनीति को यह संकेत दे दिया कि टकराव नहीं, संवाद ही आगे का रास्ता है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में अजित पवार ने पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे जैसे मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। गठबंधनों के बदलते दौर में भी अपनी उपयोगिता और असर बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी रही। अजित पवार चूंकि केंद्र और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ एनडीए के प्रमुख घटक थे इसलिए उनका निधन बड़ा राजनीतिक नुकसान भी है।

देखा जाये तो अजित पवार का जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं है, यह उस राजनीतिक शैली का अंत है जो चुपचाप काम करने में यकीन रखती थी। उनकी राजनीति प्रशासनिक पकड़, आंकड़ों की समझ और सत्ता की नस पहचानने की कला से बनी थी। शरद पवार की विशाल छाया में राजनीति शुरू करना आसान था, लेकिन उस छाया से निकलकर अपनी पहचान बनाना बेहद कठिन था। अजित पवार ने यह कठिन रास्ता चुना। वह हमेशा इस द्वंद्व में रहे कि उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाए या एक स्वतंत्र नेता के रूप में। शायद इसी बेचैनी ने उन्हें बार-बार जोखिम लेने के लिए प्रेरित किया। 2023 की वह सुबह भारतीय राजनीति के सबसे नाटकीय क्षणों में गिनी जाती है जब उन्होंने अचानक सत्ता का समीकरण बदल दिया था। उनकी काफी आलोचना हुई, अविश्वास भी पैदा हुआ, लेकिन यह भी सच है कि उसी क्षण ने उन्हें निर्णायक नेता के रूप में स्थापित किया। बाद में चुनाव आयोग का फैसला उनके पक्ष में जाना इस बात का संकेत था कि राजनीति में साहस कई बार वैधता भी दिला देता है। अजित पवार की राजनीति नैतिकता के आदर्शों की किताब से कम और यथार्थ की जमीन से ज्यादा निकली थी। यही कारण है कि वह आलोचकों के निशाने पर भी रहे और समर्थकों के भरोसे का केंद्र भी बने। वह जानते थे कि सत्ता स्थायी नहीं होती, लेकिन प्रभाव बनाया जा सकता है। उन्होंने वही किया। विभिन्न लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान मैंने खुद देखा कि वह समर्थकों और कार्यकर्ताओं के कितने करीब रहते हैं और सबकी बातें ध्यान से सुनते हैं। यही कारण था कि बारामती में खासतौर पर अजित दादा के नाम का बोलबाला हर जगह देखने को मिलता है। आज जब उनका जाना अचानक और असमय हुआ है, महाराष्ट्र की राजनीति एक खालीपन महसूस कर रही है। यह खालीपन सिर्फ पद का नहीं, उस अनुभव का है जो दशकों में गढ़ा जाता है।

आने वाले समय में यह सवाल और तीखा होगा कि क्या कोई नेता सहकार से सत्ता तक के इस रास्ते को फिर उसी धार और दृढ़ता से तय कर पाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि अजित पवार की विरासत विरोधाभासों से भरी रही, लेकिन शायद यही उनकी सच्ची पहचान भी है। वह सरल नहीं थे, पर प्रभावशाली थे। वह आदर्शवादी नहीं थे, पर निर्णायक थे। और इसी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में उनका नाम लंबे समय तक याद रखा जाएगा।

किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं के मामले में भारत ने विकसित देशों के एकाधिकार को चुनौती दी

यह कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत आज दुनिया के डॉक्टर के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। अपनी उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं, किफ़ायती दवाओं और वैश्विक संकटों में अपनी अग्रणी भूमिका के कारण भारत ने मानवता की सेवा में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।वैसे भी प्राचीन काल से ही भारत आयुर्वेद और सुश्रुत की विरासत के माध्यम से चिकित्सा जगत का मार्गदर्शक रहा है। लेकिन आधुनिक युग में, भारत ने तकनीकी प्रगति और दुनिया के स्वास्थ्य मानचित्र पर अपनी एक अनिवार्य जगह बना ली है। बीते कुछ दशकों में वैश्विक परिदृश्य पर भारत की छवि न केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सुदृढ़ हुई है, बल्कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी देश ने दुनिया के डॉक्टर का गौरवपूर्ण सम्मान प्राप्त किया है। यह बदलाव रातों-रात नहीं आया, बल्कि इसके पीछे भारत की विशाल दवा निर्माण क्षमता, अनुभवी डॉक्टरों की फौज और प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों का आधुनिक विज्ञान के साथ सटीक तालमेल है। आज जब हम वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं की बात करते हैं, तो भारत का नाम सबसे ऊपर आता है क्योंकि दुनिया भर में टीकों की कुल मांग का लगभग साठ प्रतिशत हिस्सा भारत ही पूरा करता है। किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं के मामले में भारत ने विकसित देशों के एकाधिकार को चुनौती दी है, जिससे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे गरीब देशों के आम नागरिकों तक जीवन रक्षक दवाएं पहुँचना संभव हो पाया है। विशेष रूप से एचआईवी, कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों की सस्ती दवाएं उपलब्ध कराकर भारत ने मानवताके प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को सिद्ध किया है। कोरोना महामारी के उस भयावह काल ने भारत की इस डॉक्टर वाली भूमिका को पूरी दुनिया के सामने अत्यंत स्पष्टता से रखा। जब वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य प्रणालियाँ चरमरा रही थीं और विकसित राष्ट्र अपने संसाधनों को सुरक्षित करने में लगे थे, तब भारत ने वैक्सीन मैत्री की पहल के साथ सौ से अधिक देशों को करोड़ों टीके और आवश्यक दवाएं पहुँचाकर एक सच्चे अभिभावक की भूमिका निभाई। हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन जैसी दवाओं की वैश्विक मांग को पूरा करने से लेकर खुद का स्वदेशी टीका विकसित करने तक, भारत ने यह दिखा दिया कि उसकी वैज्ञानिक प्रगति केवल मुनाफे के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए समर्पित है। आज भारत का चिकित्सा पर्यटन भी एक नए शिखर पर है। दुनिया के कोने-कोने से मरीज हार्ट सर्जरी, नी-रिप्लेसमेंट और ऑन्कोलॉजी जैसे जटिल इलाजों के लिए भारत का रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पश्चिमी देशों की तुलना में केवल दसवें हिस्से की लागत पर विश्वस्तरीय उपचार मिलता है। भारत के पास न केवल जेसीआई प्रमाणित अस्पताल हैं, बल्कि ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर भी हैं जिनकी काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। डिजिटल क्रांति ने भारत की इस ताकत को और अधिक धार दी है। कोविन जैसा विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या फिर ई-संजीवनी के माध्यम से घर-घर पहुँचने वाली टेलीमेडिसिन सेवा, भारत ने दिखाया है कि कैसे तकनीक का उपयोग करके स्वास्थ्य सेवाओं का लोकतंत्रीकरण किया जा सकता है। इसके साथ ही, भारत ने योग और आयुर्वेद के माध्यम से प्रिवेंटिव हेल्थकेयर यानी बीमारी से पहले बचाव का जो मंत्र दुनिया को दिया है, उसने पश्चिमी जगत की जीवनशैली को भी प्रभावित किया है। आज दुनिया केवल बीमारी के इलाज के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भारत की ओर देख रही है। आयुष मंत्रालय के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने की दिशा में जो काम हुआ है, उसने भारत को एक संपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र बना दिया है। भारतका दुनिया का डॉक्टर बनना महज एक नारा नहीं है, बल्कि यह देश के संस्कार, सहस और वसुधैव कुटुंबकम की उस प्राचीन भावना का प्रमाण है जो पूरे विश्व को एक परिवार मानकर उसके स्वस्थ रहने की मंगलकामना करती है। आज भारत दुनिया में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। दुनिया भर में टीकों की कुल मांग का लगभग 60फीसदी भारत द्वारा पूरा किया जाता है। अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों में एचआईवी/एड्स जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भारत ने बेहद कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराकर लाखों लोगों की जान बचाई है। विकसित देशों की तुलना में भारत में निर्मित दवाएं 30फीसदी से 50फीसदी तक सस्ती होती हैं, जो वैश्विक स्वास्थ्य असमानता को कम करने में मदद करती है। पांच वर्ष पूर्व कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की भूमिका ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ समझाया।जब दुनिया के बड़े देश दवाओं के संरक्षण में लगे थे, तब भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत सौ से अधिक देशों को करोड़ों टीके भेजे। हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन और पैरासिटामोल जैसी आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करके भारत ने एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में कार्य किया। भारत के फार्मा उद्योगों की दवाएं अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली आदि देशों में निर्यात की जाती हैं। कुछ अफ्रीकी, दक्षिण-पूर्व एशियाई और मध्य-पूर्व के देशों में भी दवाओं की आपूर्ति की जाती है। सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डा. रेड्डीज लैबोरेट्रीज लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, जायडस लाइफ साइंसेज, लूपिन लिमिटेड, इंटास फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बायोकान लिमिटेड, एबाट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लेनमार्क फार्मा लिमिटेड, अल्केम लैबोरेट्रीज लिमिटेड, एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, अरिस्टो फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, टोरेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड व मैंकिलयोड्स फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड जैसे उद्योग यहां दवा उत्पादन कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें दवा उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में खूब प्रयास कर रही हैं। यही वजह है कि कच्चे माल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी ठोस प्रयास हो रहे हैं। चीन पर निर्भरता घटाने के लिए बल्क ड्रग पार्क की स्थापना और नीति समर्थन यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले वर्षों में भारत न केवल दवाओं का, बल्कि उनके कच्चे माल का भी बड़ा वैश्विक केंद्र बनेगा। आज भले ही हिमाचल प्रदेश में दवा उत्पादन का मात्र दो प्रतिशत कच्चा माल उपलब्ध हो, लेकिन अगले पांच वर्षों में देश में 60 प्रतिशत से अधिक कच्चा माल स्वदेशी होने की उम्मीद भारत के स्वास्थ्य भविष्य को और सुदृढ़ बनाती है। भारत की उपलब्धि इसलिए भी गौरवपूर्ण है, क्योंकि यहां बनी दवाएं विकासशील ही नहीं, बल्कि विकसित देशों के स्वास्थ्य तंत्र का भी भरोसा हैं।

सस्ती, प्रभावी और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरने वाली भारतीय दवाओं ने यह सिद्ध किया है कि भारत केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य का संरक्षक है। जीएसटी लागू होने के बाद कर छूट समाप्त होने से कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचे, बिजली, परिवहन, औद्योगिक शेड, तकनीकी स्टाफ और लेबर की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इससे दवा उत्पादन आसान हुआ है और हिमाचल प्रदेश के साथ भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आज भारत विश्व स्तर पर चिकित्सा पर्यटन के लिए सबसे पसंदीदा स्थलों में से एक है। इसके पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित हैंःउच्च गुणवत्ता वाले अस्पतालः भारत में जेसीआई और एनएबीएच प्रमाणित अस्पतालों की भरमार है। लागत में भारी अंतरः अमेरिका या यूरोप में होने वाले ऑपरेशनों (जैसे हार्ट बाईपास या नी रिप्लेसमेंट) की तुलना में भारत में इसका खर्च लगभग 1/10वां हिस्सा होता है।विशेषज्ञताः भारतीय डॉक्टरों की कुशलता को पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है। भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक का उपयोग कर एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। को- विन प्लेटफॉर्मः भारत के डिजिटल टीकाकरण अभियान ने दुनिया को दिखाया कि बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य डेटा का प्रबंधन कैसे किया जाता है।टेलीमेडिसिनः ई-संजीवनी जैसे पोर्टल्स के माध्यम से दूर-दराज के इलाकों तक विशेषज्ञ सलाह पहुँचाने के मॉडल को अब दुनिया अपना रही है।भारत केवल एलोपैथी तक सीमित नहीं है। भारत ने आयुष मंत्रालय के माध्यम से योग और आयुर्वेद को वैश्विक मंच पर पुनर्जीवित किया है। आज दुनिया प्रिवेंटिव हेल्थकेयर के लिए भारत की ओर देख रही है। भारत का दुनिया का डॉक्टर बनना केवल आर्थिक लाभ का विषय नहीं है, बल्कि यह सेवा और करुणा की भावना से प्रेरित है। अपनी वैज्ञानिक क्षमता और नैतिक जिम्मेदारी के बल पर भारत ने सिद्ध किया है कि वह न केवल अपने 140 करोड़ नागरिकों की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि पूरी मानवता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वे सन्तु निरामयाः (सभी रोगमुक्त रहें) - यही भारत का वैश्विक संदेश है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार घारो ने कदम ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पॅनतवाला एस्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार घारो, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/...)

गांवों का समग्र विकास चाहती है केन्द्र सरकार: रामवीर सिंह

मुरादाबाद।

ब्लॉक सभागार मूंढापांडे में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक में शामिल ग्राम प्रधानों और रोजगार सेवकों को अधिनियम के बारे में बताते हुए विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मंशा अनुरूप प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा यह कानून विकसित भारत जी राम जी लाया गया है। विकसित भारत जी राम जी बिल गांव की समग्र विकास की बेहतर कार्ययोजना तैयार करने का आधार बनेगा। इसके जरिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वावलंबी भारत के निर्माण का स्वपन भी पूरा होगा। जी राम जी के माध्यम से ग्राम पंचायतें गांव के विकास के लिए कार्य का स्वनिर्धारण कर स्वयं इसका क्रियान्वयन भी करेंगी। केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व के मनरेगा योजना को संशोधित कर नवीन रूप में और सशक्त बनाया गया है। यह विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में मददगार होगा। साथ ही पारदर्शी तरीके से श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान प्राप्त होगा और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। इसमें 100 दिवस के स्थान पर 125 दिन काम देने का प्रावधान है। इसके अलावा अब स्थायी स्ट्रक्चर निर्माण के कार्य को भी जोड़ा गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को इसके लिए बजट पारित करने का अधिकार भी मिलेगा। जी राम जी बिल के संबंध में व्याप्त भ्रांति और भ्रम का समाधान करते हुए बताया कि इसके लागू होने के बाद फर्जी मस्टर रोल की प्रवृत्ति से निजात मिलेगी। सात दिवस में हितग्राही के खाते में मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित होगा और आवेदन देने के 15 दिवस में काम न मिलने पर बेराजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी है। आप दोनों ग्राम विकास की अहम् कड़ी है, आपके माध्यम से गांव में जन जन तक विकसित भारत जी राम जी की सही जानकारी पहुँचनी चाहिए। बैठक में ब्लॉक प्रमुख मूंढापांडे डॉ नवदीप यादव, रामकिशोर लोधी , बीडीओ अशोक कुमार, एडीओ अमरीश यादव, सतीश प्रजापति, भानु प्रताप, योगेश तोमर ,सतीश सैनी सहित समस्त ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक एवं रोजगार सेवक उपस्थित रहे।

शान्त माहौल में सम्पन्न हुआ बार कौंसिल सदस्य का चुनाव

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के 25 सदस्यीय चुनाव के तहत बुधवार को कचहरी परिसर में मतदान के दूसरे दिन की प्रक्रिया शान्त माहौल में सम्पन्न हुई। सुबह से ही अधिवक्ता मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे। बार काउंसिल सदस्य पद के लिए मुरादाबाद से चुनाव मैदान में उतरे अधिवक्ता सुभाष माथुर, राकेश कुमार वाशिष्ठ और आदित्य राघव के समर्थन में कचहरी परिसर में चहल-पहल बनी रही। यूपी में 333 सीट से होने वाले इस चुनाव में मुरादाबाद के तीन प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें राकेश वशिष्ठ , सुभाष चंद्र माथुर और आदित्य राघव शामिल हैं। स्थानीय प्रत्याशियों के मैदान में होने के कारण मुरादाबाद के अधिवक्ताओं में चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखा गया। मतदान केंद्र पर युवा, बुजुर्ग और महिला अधिवक्ता बड़ी संख्या में पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अधिवक्ताओं में सुबह से ही जोश और सक्रियता नजर आई, जिससे कलेक्ट्रेट परिसर में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। ठाकुरद्वारा और मुरादाबाद शहर को मिलाकर कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3,976 बताई जा रही है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदान स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई थी। कुल मिलाकर मुरादाबाद में बार काउंसिल चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला।

रामगंगा विहार से चोरी हुई क्रेटा कार पुलिस ने की बरामद, शातिर ऑटों लिफ्टर को किया गिरफ्तार

मुरादाबाद।

सिविल लाइंस थाना पुलिस ने वाहन चोरी के एक मामले में सफलता हासिल की है। पुलिस ने रामगंगा विहार फेस-2 से चोरी हुई हुंडई क्रेटा कार बरामद कर एक शातिर वाहन चोर इस्लामुद्दीन को गिरफ्तार किया है। यह घटना 21 जनवरी को हुई थी, जब रामगंगा विहार फेस-2 से एक क्रेटा कार (यूके 18 एन 4415) चोरी हो गई थी। वाहन मालिक मनोज कपूर की शिकायत पर सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस टीम ने लगातार जांच और निगरानी के बाद 27 जनवरी को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की।

पुलिस को सूचना मिली थी कि चोरी की कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर दो व्यक्ति वेव सिनेमा के पीछे घूम रहे हैं। इस पर पुलिस ने घेराबंदी की और कार को रोकने का प्रयास किया। ड्राइवर भागने लगा, जबकि दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से इस्लामुद्दीन को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान कार से असली नंबर प्लेट, दो फर्जी नंबर प्लेट, 1,100 रुपये नकद, एक मोबाइल फोन और दो आधार कार्ड बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी इस्लामुद्दीन ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथी अजय उर्फ सोनू के साथ मिलकर यह कार चोरी की थी। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी इस्लामुद्दीन पर दिल्ली में वाहन चोरी के 11 से अधिक मामले दर्ज हैं। फरार आरोपी अजय की तलाश जारी है। इस कार्रवाई में इंस्पेक्टर मनीष सक्सेना, सब-इंस्पेक्टर सचिन कुमार, आकाश धामा, और कांस्टेबल बाबर व सनी पवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अधिकारियों ने इस गिरफ्तारी को वाहन चोरी रोकने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया है।

नेपाली मूल की अवैध देशी शराब के साथ महिला गिरफ्तार

सिद्धार्थनगर। राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी गोरखपुर के अंतर्गत जीआरपी चौकी सिद्धार्थनगर थाना आनंदनगर ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत एक महिला शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। अभियुक्ता के कब्जे से नेपाली मूल की अवैध देशी शराब बरामद की गई है।

यह कार्रवाई अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे श्री प्रकाश डी, पुलिस महानिरीक्षक रेलवे लखनऊ रामकृष्ण भारद्वाज के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक रेलवे लक्ष्मी निवास मिश्र के मार्गदर्शन में की गई है। पुलिस उपाधीक्षक रेलवे गोरखपुर विनोद कुमार के निकट पर्यवेक्षण में जीआरपी चौकी सिद्धार्थनगर की टीम ने यह सफलता हासिल की। पुलिस के अनुसार, रेलवे स्टेशन सिद्धार्थनगर के महिला टीन शेड के पास से अभियुक्ता गुड़िया पत्नी चन्द्रभान निषाद, निवासी परसा रेलवे स्टेशन के पास थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर (उम्र लगभग 48 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के पास से एक झोले में 20 अदद नेपाली अवैध देशी शराब (प्रत्येक 300 एमएल) बरामद हुई, जिसकी कुल मात्रा 6 लीटर एवं अनुमानित कीमत लगभग 1,000 रुपये बताई गई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के उपरांत अभियुक्ता के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 01/26, धारा 60(63) आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ के दौरान अभियुक्ता ने बताया कि वह अपना खर्च चलाने के लिए उत्तर प्रदेश से ट्रेनों के माध्यम से शराब लेकर बिहार राज्य में लगभग दो गुने दाम पर बेचती थी। आज भी वह अवैध रूप से शराब लेकर बिहार जाने की फिराक में थी, तभी जीआरपी टीम ने उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक सुग्रीव कुमार जीआरपी चौकी सिद्धार्थनगर, मुख्य आरक्षी बृजेश यादव जीआरपी थाना आनंदनगर, आरक्षी विवेक यादव जीआरपी चौकी सिद्धार्थनगर, आरक्षी देवेंद्र यादव जीआरपी थाना आनंदनगर, आरक्षी दुर्गेश यादव जीआरपी थाना आनंदनगर, महिला कर्मी सुभाषनी शामिल रही।

दिल्ली रोड से नगर निगम ने हटवाया अतिक्रमण

मुरादाबाद। नगर निगम की टीम ने बुधवार को दिल्ली रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। शुरुआत चौधरी चरण सिंह चौक से की गई। इसके बाद टीम के द्वारा गागन तिराहा तक अभियान चलाया गया। गागन के पास कुछ लोगों के द्वारा फुटपाथ पर कब्जा किया गया था। सभी का पांच-पांच सौ रुपये का चालान काटा गया। हिदायत दी गई की दोबारा फुटपाथ पर कब्जा किया गया तो मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि फुटपाथ लोगों के चलने के लिए बनाया गया है। अतिक्रमण न किया जाए। निगम लगातार अभियान चलाएगा।

स्वयंसेवकों ने मतदान को लेकर किया जागरूक

मुरादाबाद। चित्रगुप्त इण्टर कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वावधान में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निबंध, स्लोगन प्रतियोगिता एवं मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन ग्राम मोरा मुस्तकम में हुआ। छात्रों ने स्लोगन, निबन्ध के माध्यम से मतदान के महत्व को समझाया। बाद में ग्राम में मतदाता रैली निकालकर ग्राम वासियों को वोट बनवाने एवं अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने एवं करवाने का संदेश दिया। कार्यक्रम अधिकारी डॉ राजीव कुमार ने बताया कि जब नागरिक मतदान करते हैं, तो वे स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। चुनाव मतदाताओं को नेताओं को चुनौती देने और उन्हें जवाबदेह ठहराने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक समूह अत्यधिक शक्तिशाली या जवाबदेही से मुक्त न हो जाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता द्वितीय कार्यक्रम अधिकारी डॉ विशेष कुमार शर्मा ने की। इस अवसर पर शोर्य कुमार, यशराज सिंह,देव,फैज खान, अरमान,अंश,शिवा, रोहित कुमार, वासुदेव ने सहयोग किया।

सूफी अम्बा प्रसाद को दिया जाये भारत रत्न

मुरादाबाद। आईना-ए-उर्दू सहाफत के सम्पादक मुर्तजा इकबाल ने स्वतंत्रता सेनानी सूफी अम्बा प्रसाद को भारत रत्न दिये जाने की वकालत की है। उन्होंने इस संबंध में मण्डलायुक्त को एक ज्ञापन भी दिया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सूफी अम्बा प्रसाद के बलिदानी चरित्र एवं क्रान्तिकारी पत्रकारिता को जो महत्व प्रदान किया जाना चाहिये था वह नहीं दिया जा सका। अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि गवर्मेन्ट कालिज चौराहे पर सूफी अम्बा प्रसाद की मूर्ति न लगाया जाना एवं चौराहे को सूफी अम्बा प्रसाद चौक घोषित न किया जाना प्रशासनिक उदासीनता एवं पक्षपात का प्रतीक है। उन्होंने का कि सूफी अम्बा प्रसाद को उनके त्याग, संघर्ष एवं बलिदानों एवं जान हथेली पर रखकर की गई क्रान्तिकारी पत्रकारिता के परिदृश्य में उन्हें भारत रत्न देने की संस्तुति की जाना आवश्यक है इसके साथ ही नगर निगम मुरादाबाद द्वारा स्वीकृत राजकीय इन्टर कालिज चौराहे का नाम सूफी अम्बा प्रसाद चौक घोषित करके वहां उनके नाम का पत्थर लगाया जाये और उनकी मूर्ति स्थापित की जाये।

फुल मैराथन में इथोपिया के फिरोनिशा ने मारी बाजी

*हाफ मैराथन में पंकज व दस में प्रिंस राज मिश्र तथा पांच किमी दौड़ में सोनी रहे अव्वल

बलिया।

द्वाबा के मालवीय पूर्व विधायक मैनेजर सिंह की जयंती पर आयोजित 42.195 किमी के फुल मैराथन में अफ्रीकी देश इथोपिया के निवासी फिरोनिशा ने प्रथम स्थान हासिल किया। फिरोनिशा ने कुल 2 घंटे 8 मिनट में दौड़ पूरा किया। इनके बाद पहुंचे मुजफ्फरनगर के अक्षय कुमार द्वितीय व दिल्ली के अमरेश प्रजापति ने तृतीय स्थान हासिल किया। इसके अलावा हाफ मैराथन 21 किमी में वाराणसी के पंकज कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसमें अयोध्या के प्रिंसराज यादव द्वितीय व आगरा के मनीष सिंह ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। दस किमी में प्रिंस राज मिश्र प्रथम वाराणसी के आशीष पाल तथा बलिया राकेश वर्मा ने द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं 5 किलोमीटर में वाराणसी की सोनी प्रथम व वाराणसी की ही लक्ष्मी चौहान द्वितीय तथा रूबी पाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मैराथन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले फिरोनिशा को प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने 2.25 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया। इसमें दूसरे स्थान पर आए अक्षय कुमार को 1.25 लाख व अमरेश प्रजापति को 75 हजार रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। हाफ मैराथन में प्रथम विजेता को 65 हजार व द्वितीय को 45 हजार व तृतीय को 30 हजार रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। 10 किमी की दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को

25 हजार द्वितीय को 15 हजार व तृतीय को 10 हजार रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। 5 किमी की दौड़ प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार 11 हजार व द्वितीय को 7 हजार तथा तृतीय को 5 हजार की राशि प्रदान की गई। इसके अलावा सभी श्रेणियों में 50वें स्थान तक आए प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार राशि दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 8-00 बजे वीर लोरिक स्टेडियम मंत्री द्वय गिरीश चंद्र यादव व दयाशंकर सिंह तथा जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर किया। मैराथन का समापन बैरिया स्थित बाबू मैनेजर सिंह की प्रतिमा स्थल पर जाकर संपन्न हुआ। हाफ मैराथन हल्दी भरसौता पेट्रोल पंप के पास संपन्न हुआ। 10 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता जनाड़ी तक तथा 5 किलोमीटर की कदम चौराहा पर संपन्न हुआ। सभी विजेताओं को पुरस्कार राज बैरिया सुदिष्टपुरी स्थित सुदिष्ट बाबा स्कूल पर प्रदान किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि यह पूरे जनपद के लिए गौरव की बात है। यह प्रदेश का चौथा मैराथन है जो इतनी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। आने वाले वर्ष में इस आयोजन को और भी भव्य रूप प्रदान किया जाएगा।

कहा कि बलिया का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है और यहां के लोग अपनी प्रतिभा के दम पर पूरे विश्व में अमिट छाप बनाए हुए हैं। द्वाबा के मालवीय कहे जाने वाले बाबू मैनेजर सिंह की जयंती पर आयोजित यह कार्यक्रम सभी के लिए प्रेरणादायी रहेगा। कहा कि आज भाजपा सरकार में ही खेल को इतना महत्व दिया जा रहा है। बलिया में खेल से संबंधित जो भी डिमांड होगा उसे प्राथमिकता पर पूरा किया जाएगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि मेरे मामा मैनेजर सिंह की जयंती पर आयोजित यह मैराथन पूरे जनपद के सहयोग से सकुशल संपन्न हुआ। यह आयोजन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा।

कहा कि युवाओं के लिए जिले में कई स्तर पर विकास के मानचित्र को तैयार किया गया है जो आगे आने वाले दिनों में स्पष्ट दिखाई देगा। प्रदेश सरकार के सहयोग से जिले में विकास के कई कार्यों को कराया जा रहा है और आगे भी जो कार्य आम जनमानस के जनहित में होगा उसे निश्चित तौर पर पूरा किया जाएगा।

***मैनेजर सिंह की प्रतिमा पर हुई माल्यार्पण**

इस दौरान बैरिया तिराहे पर स्थित बाबू मैनेजर सिंह की प्रतिमा स्थल पर लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मंत्रीद्वय गिरीश चंद्र यादव व दयाशंकर सिंह ने उनकी प्रतिमा पर माला चढ़कर उन्हें नमन किया। इस दौरान द्वाबा क्षेत्र के लोगों ने बैरिया तिराहे पर अतिथियों का जोरदार स्वागत किया।

***बलिया के हर ब्लाक में बनेगा स्टेडियम**

- खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि बलिया के हर ब्लाक में स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया है। यही नहीं प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में 40 मिनट का खेल प्रतियोगिता अनिवार्य किया गया है। आज प्रदेश में सभी नेशनल पदक विजेताओं को नौकरी दी जा रही है। बलिया का स्पोर्ट्स कालेज भी जल्द तैयार होगा। इसके लिए जो भी बजट लगेगा उसे दिया जाएगा।

***परिवहन मंत्री ने दो धावकों को दिए 50-50 हजार**

- मैराथन में सबसे अधिक उम्र के धावक चौरा कथरिया निवासी 70 वर्षीय चंद्र भान सिंह व 21 किमी तक दौड़ा बेलहरी निवासी कक्षा तीन के छात्र कार्तिक राजभर को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अलग से सम्मानित किया। मंत्री ने दोनों धावकों को 50-50 हजार रुपए का पुरस्कार दिया।

तीन साल बाद जनवरी में सबसे अधिक बादल बरसे, 1 फरवरी को बारिश की संभावना

नई दिल्ली। राजधानी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बीते तीन साल बाद जनवरी में अबतक सबसे अधिक मेघ बरसे है। मौसम विभाग के अनुसार, इस माह में अब तक 21.01 मिमी बारिश हो चुकी है। इससे पहले 23 और 24 जनवरी की सुबह 8-30 बजे तक सफदरजंग मानक वेधशाला में 19.8 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। वहीं, साल 2025 में 8.3, 2024 में बारिश ट्रेस और 2023 में 20.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इसके अलावा, ऑल टाइम रिकॉर्ड साल 1885 का है, जब 173.2 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। हालांकि, मौसम विभाग ने अब महीने के अंत तक बारिश नहीं होने की संभावना जताई है। ऐसे में बुधवार को पारा गिर सकता है। इससे ठिठुरन बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 28 जनवरी से 2 फरवरी तक मौसम ठंडा और बादल वाला रहने का अनुमान है। 28 जनवरी से 30 जनवरी तक अधिकतर बादल छाए रहेंगे और सुबह हल्का कोहरा रहेगा। 29 जनवरी को मौसम आंशिक रूप से बादल वाला रहेगा। 31 जनवरी को भी आंशिक बादल

रहने के साथ हल्का कोहरा रहेगा। 1 फरवरी को आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार हल्की बारिश के साथ गरज और बिजली कड़कने की संभावना है। दिल्ली में मंगलवार को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसके चलते से ठंड बढ़ गई है। बीते सोमवार को अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहने के बाद मंगलवार को बारिश से तापमान में गिरावट हुई।

इससे एक बार फिर से सर्दी की वापसी हो गई है। मंगलवार को नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली में फिर मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह नौ बजे ही अंधेरा छा गया और रात का अहसास होने लगा। ऐसे में कुछ देर बाद ही बारिश शुरू हो गई। इस दौरान दिल्ली के कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे कड़ाके की ठंड लौट आई। इस दौरान तेज बर्फीली हवाओं ने लोगों को सिहरन महसूस कराई। इससे दृश्यता भी कम रही। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मंगलवार को पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई थी।

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दुखी मन से छोड़ा माघ मेला, बोले- ऐसी कल्पना कभी नहीं की थी

प्रयागराज। मौनी अमावस्या के दिन माघ मेले में हुई कथित मारपीट की घटना को लेकर जारी विवाद के बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रयागराज माघ मेला छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बुधवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मन अत्यंत दुखी होने के कारण वह बिना संगम स्नान किए ही काशी लौट रहे है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि प्रयागराज सदैव आस्था और शांति की भूमि रही है। श्रद्धा के साथ यहां आए थे, लेकिन एक ऐसी घटना घटित हुई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। इस घटना ने उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया है और न्याय व मानवता के प्रति उनका विश्वास कमजोर हुआ है। उन्होंने बताया कि माघ मेला प्रशासन की ओर से उन्हें एक पत्र और प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें पूरे सम्मान के साथ पालकी द्वारा संगम ले जाकर स्नान कराने की बात कही गई थी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि जब मन में दुख और आक्रोश हो, तब पवित्र संगम जल भी शांति प्रदान नहीं कर पाता। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि प्रशासन सुविधाएं देकर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मौनी अमावस्या की घटना और कथित मारपीट पर एक शब्द भी नहीं कहा गया। उन्होंने इसे लोभ और लालच करार देते हुए कहा कि इससे उनकी अंतरात्मा को गहरी चोट पहुंची है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की नीयत अभी भी ठीक नहीं है और सरकारी सुविधाएं देकर संतों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कारण उन्होंने माघ मेला छोड़ने का निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि माघ मेला 15 फरवरी तक चलना है, जबकि अभी दो प्रमुख स्नान पर्व माघी पूर्णिमा (1 फरवरी) और महाशिवरात्रि (15 फरवरी) शेष हैं। विवाद के चलते शंकराचार्य ने 18 दिन पूर्व ही माघ मेला छोड़ दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख है और इससे सनातन धर्मियों को गहरी पीड़ा पहुंची है। उन्होंने कहा कि हार-जीत का निर्णय समय करेगा और इस विषय पर अंतिम फैसला सनातन धर्म की जनता लेगी।

किसी के निधन पर घटिया राजनीति करना दुखद : ममता बनर्जी पर भड़के फडणवीस, बोले- ओछी राजनीति कर रहीं बंगाल की सीएम

मुंबई।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन को लेकर दिए गए बयान पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनके बयान की कड़ी आलोचना की है।

मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए- फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह बेहद दुख की बात है कि किसी की मौत पर इस तरह की राजनीति की जा रही है। उन्होंने याद दिलाया कि वरिष्ठ नेता शरद पवार स्वयं स्पष्ट कर चुके हैं कि यह एक हादसा था, जिसमें दुखद रूप से जानें गईं, और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फडणवीस ने आगे कहा, किसी के निधन पर गंदी और घृणित राजनीति करना बेहद दुखद है। ममता दीदी का इस स्तर तक गिरना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है। महाराष्ट्र के एक प्रिय और सम्मानित नेता के निधन को इस तरह राजनीतिक रंग देना पूरी तरह अनुचित है।

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने भी ममता पर साधा निशाना

वहीं, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी ममता बनर्जी के बयान को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि ऐसी दुखद घटनाओं के समय राजनीति करना उचित नहीं है। शिंदे ने कहा, इस हादसे को लेकर साजिश के संकेत देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। शरद पवार साहब ने साफ कहा है कि यह केवल एक दुर्घटना थी, इसमें कोई

साजिश नहीं है। शिंदे ने आगे कहा कि पूरा महाराष्ट्र शोक में डूबा हुआ है और अंतिम दर्शन के दौरान हजारों-लाखों लोग 'अजित दादा, अजित दादा' के नारे लगाते नजर आए। ऐसे समय में आरोप लगाना न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे महाराष्ट्र की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए और भी कई मौके होते हैं, लेकिन शोक की घड़ी में इस तरह के बयान बिल्कुल गलत है।

ममता बनर्जी के इस बयान से मचा सियासी संग्राम

दरअसल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुबह अजित पवार की मृत्यु की खबर सुनकर वो स्तब्ध रह गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि इस देश में राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है। आज सत्तारूढ़ वर्ग का हिस्सा रहे लोग भी सुरक्षित नहीं दिखते। आगे उन्होंने कहा कि मामले की जांच तो होनी चाहिए क्योंकि ऐसा हादसा हुआ है। सभी नेता विमान से जाते हैं, कॉरपोरेट के लोग भी जाते हैं। यह छोटा विमान था, ऐसा क्यों हुआ, इसकी जांच तो होनी चाहिए।

मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए- शरद पवार

शरद पवार ने भतीजे और राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में हुई मौत पर बयान देते हुए कहा कि यह पूरी तरह एक दुर्घटना है। इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि यह परिवार और राज्य के लिए गहरा आघात है। पूरे परिवार और राज्य के लिए यह अपूरणीय क्षति है। यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। उन्होंने सभी से अपील की कि इस हादसे को राजनीतिक रंग न दिया जाए। इस समय परिवार और प्रियजनों का समर्थन करना सबसे जरूरी है।

राष्ट्रपति का अभिभाषण नीरस और खोखले वादों से भरा था : कांग्रेस

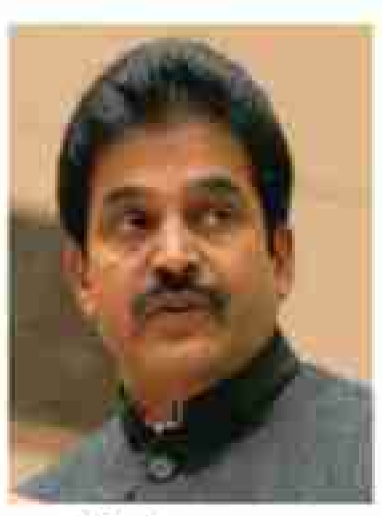

नई दिल्ली।

कांग्रेस ने बुधवार को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के बाद नरेन्द्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र द्वारा तैयार किया गया भाषण नीरस और खोखले वादों से भरा था। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, ''कुछ भी नया नहीं था, सिर्फ उन चीजों का दोहराया गया जो वह पहले की चुकी है। उन्होंने दावा किया, ''सरकार द्वारा तैयार किया गया पूरी तरह से खोखला भाषण है। सरकार के खोखले वादे बार-बार दोहराए गए है। राष्ट्रपति द्वारा नए विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम का उल्लेख किए जाने पर विपक्ष के हंगामे पर उन्होंने कहा, ''हमने उस समय विरोध किया था। हम पहले से ही इस कानून को वापस लेने के लिए आंदोलन कर रहे है। इसलिए मैंने कहा कि ये केंद्र सरकार के खोखले वादे हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, ''माननीय राष्ट्रपति इस अभिभाषण देने के लिए केवल सरकार की प्रवक्ता है। अभिभाषण सरकार द्वारा लिखा जाता है और कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तिवारी ने कहा, ''उन परिस्थितियों में, यह एक नीरस संबोधन था। इसमें कोई दृष्टिकोण नहीं रखा गया, केवल सरकार की कथित उपलब्धियों की एक सूची पढ़ी गई।

संसद के दोनों सदनों में पवार को श्रद्धांजलि; राष्ट्रपति मूर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज

नई दिल्ली। बुधवार दोपहर दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई और कल (गुरुवार) सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों ने सराहना व्यक्त करते हुए मेजें थपथपाईं, वहीं विपक्षी सांसद खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कानून को वापस लेने की मांग करने लगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र 2026-27 के पहले दिन संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और विकसित भारत के लिए केंद्र सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। राष्ट्रपति ने लोकसभा के 18वें सत्र और राज्यसभा के 270वें सत्र के उद्घाटन दिवस पर लोकसभा कक्ष में एकत्रित दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया। विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 (G

बजट सत्र 2026-27 की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संयुक्त सत्र में अभिभाषण से हुई, जिसमें उन्होंने विकसित भारत, सामाजिक न्याय और 125 दिनों की ग्रामीण रोजगार गारंटी पर सरकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। सदन की कार्यवाही विपक्षी विरोध के बीच स्थगित कर दी गई और अब गुरुवार को फिर से शुरू होगी।

RAM-G विधेयक) पर बोलते हुए मुर्मू ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत-G RAM-G कानून बनाया गया है। इस नए सुधार के साथ, गांवों में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी होगी। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें

प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछला वर्ष भारत की तीव्र प्रगति और समृद्ध विरासत का उत्सव मनाने के लिए यादगार रहा।

उन्होंने उल्लेख किया कि पूरे देश में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया और नागरिकों ने बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि देश ने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस मनाया। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर पूरे देश ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और आदिवासी समुदाय के प्रति उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती से संबंधित कार्यक्रमों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत किया। पूरे देश ने देखा कि भारत रत्न भूपेन हजारिका की जयंती समारोह ने देश को संगीत और एकता की भावना से भर दिया। जब देश अपने पूर्वजों के योगदान को याद करता है, तो नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है, जो हमें विकसित भारत की ओर ले जाने वाले हमारे सफर को और गति प्रदान करती है।

इस सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करते हुए, राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि बाबासाहेब अंबेडकर ने लगातार समानता और सामाजिक न्याय पर बल दिया, जो संविधान में निहित मूल्य है। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के अपने सभी अधिकार मिलने चाहिए। मेरी सरकार सच्चे सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इसके परिणामस्वरूप, पिछले एक दशक में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले है और सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबों को सशक्त बनाने के प्रयासों को और तेज किया जा रहा है।

मेरी सरकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासी समुदाय और सभी के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास का दृष्टिकोण प्रत्येक नागरिक के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। 2014 की शुरुआत में, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं केवल 25 करोड़ नागरिकों तक ही पहुंच पाई थीं। सरकार के प्रयासों से अब लगभग 95 करोड़ भारतीयों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

यूजीसी के समानता नियमों की Constitutional Validity पर बहस, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की, क्योंकि शैक्षणिक परिसरों में जाति-आधारित भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए ढांचे को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी राहुल दीवान की ओर से अधिवक्ता पार्थ यादव ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के समक्ष याचिका का जिक्र किया। यादव ने अदालत से मामले पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह करते हुए कहा कि नियमों के लागू होने से भेदभाव होगा और इस मुद्दे पर तत्काल न्यायिक जांच की आवश्यकता है। अनुरोध का जवाब देते हुए, मुख्य न्यायाधीश कांत ने सुनवाई की तारीख जल्द तय करने पर विचार करने की सहमति जताई और वकीलों से याचिका में मौजूद सभी खामियों को दूर करने को कहा ताकि मामले को सूचीबद्ध किया जा सके।

दीवान की याचिका उन कम से कम तीन चुनौतियों में से एक है जो 2026 के नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इन नियमों को यूजीसी ने

13 जनवरी को अधिसूचित किया था और इसके तहत 2012 के ढांचे को प्रतिस्थापित किया गया था।

इनमें से एक याचिका उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पोस्ट-डॉक्टरल शोधकर्ता मृत्युंजय तिवारी ने दायर की है।

दूसरी याचिका मंगलवार सुबह अधिवक्ता विनीत जिंदल ने दायर की। अदालती कार्यवाही यूजीसी द्वारा अधिसूचित नए समानता नियमों पर चल रही व्यापक राष्ट्रीय बहस की पृष्ठभूमि में हुई। इन नियमों के तहत विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और मान्यता प्राप्त संस्थानों में भेदभाव की शिकायतों के निवारण और समावेश को बढ़ावा देने के लिए समान अवसर केंद्र और समानता समितियां स्थापित करना अनिवार्य है। ये नियम अगस्त 2019 में उच्च शिक्षा में भेदभाव-विरोधी सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग वाली सर्वोच्च न्यायालय की याचिका का परिणाम है। जहां हाशिए पर रहने वाले छात्र समूहों ने इस ढांचे का स्वागत किया है, वहीं कई उच्च जाति के संगठनों और छात्रों ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि ये नियम अस्पष्ट है और इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। मंगलवार को कुछ उच्च जाति के छात्रों ने दिल्ली स्थित यूजीसी मुख्यालय के बाहर नियमों को वापस लेने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

अजित पवार का आज सुबह 11 बजे बारामती में अंतिम संस्कार

मुंबई।

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार का विमान हादसे में निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार आज (गुरुवार) सुबह 11 बजे होगा. अजित पवार के अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पहले ही बारामती पहुंच चुके है. कहा जा रहा है कि इस मौके पर पीएम मोदी भी बारामती जा सकते है. आपको बता दें कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ था. विमान क्रैश-लैंडिंग करते ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था. इस हादसे में पांच लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें तीन यात्री और दो पायलट शामिल हैं.

सुबह हुआ था हादसा

यह हादसा सुबह 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर हुआ, जब उनका चार्टर विमान लैंड करने वाला था. इस हादसे के बाद पूरे

देश में शोक की लहर है. एनसीपी (अजित गुट) के मुख्य प्रवक्ता ब्रज मोहन श्रीवास्तव ने इस हादसे को लेकर कहा कि अजित दादा के विमान हादसे की जांच करवाई जाए, ताकि देश-दुनिया को पता चले कि ये हादसा कैसे हुआ. वहीं, इससे पहले कांग्रेस ने भी ऐसी ही मांग की थी. नागपुर से कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नितिन राउत ने इस दुर्घटना की हाई लेवल जांच की भी मांग की है. उनका कहना है कि इस तरह की दुर्घटनाओं को अत्यंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए.

कैसे हुआ प्लेन क्रैश?

अजित पवार का विमान सुबह 8 बजकर 45 मिनट पर बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था. इस विमान अजित पवार के साथ एक पीएसओ, एक अटेंडेंट और दो क्रू मेंबर सवार थे. सभी का निधन हो गया. बताया जा रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव के बाद बारामती में अजित पवार की एक रैली होनी थी. उसके लिए ही अजित पवार बारामती आ रहे थे.

एएआइबी करेगी क्रैश की जांच

इस विमान की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम करेगी. बताया जा रहा है कि टीम जल्द ही घटनास्थल का दौरा करने वाली है. विमान कैसे क्रैश हुआ, इसके कारणों की तलाश की जाएगी. सूत्रों के अनुसार, डीजीसीए की टीम भी जल्द ही घटनास्थल का दौरा भी कर सकती है।

अलग रास्ता चुना, लेकिन रिश्ते नहीं तोड़े : उद्धव ठाकरे ने अजित पवार की मौत पर शोक जताया

मुंबई। शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को एक विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत पर शोक जताया और कहा कि राकांपा प्रमुख ने भले ही राजनीति में अलग रास्ता चुन लिया था, लेकिन उन्होंने आपसी रिश्तों को कभी खराब नहीं होने दिया। उद्धव ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि पवार की मौत से उन्होंने एक दृढ़ नेता और उत्कृष्ट पूर्व कैबिनेट सहयोगी खो दिया है। उन्होंने लिखा कि वित्त मंत्री के रूप में पवार एक बेहद अनुशासित नेता थे, जिनकी अपने विभाग पर मजबूत पकड़ थी। पवार ने महाराष्ट्र में 2019 से 2022 तक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार में उपमुख्यमंत्री के रूप में सेवाएं दी थी। हालांकि, वह 2023 में एमवीए से अलग हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-

नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल हो गए थे, जिससे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) दो हिस्सों में बंट गई थी। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख ने कहा, सहयोगी होने के नाते हमारे बीच एक खास रिश्ता बन गया था। अजित पवार खुले दिल के थे। वह बेबाक रह सकते थे। वह किसी से लंबे समय तक बैर नहीं रखते थे। अजित पवार ने भले ही राजनीति में अलग राह चुनी, लेकिन उन्होंने हमारे रिश्ते को टूटने नहीं दिया।उद्धव ने ठाकरे परिवार और शिवसेना (उबाठा) की ओर से अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अजित पवार एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते थे, जो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को महत्व देते थे और वह वास्तव में एक 'दादा' थे। उद्धव के बेटे और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने पवार की मौत को स्तब्ध करने वाली घटना बताया। उन्होंने कहा, मेरे पास अपनी भावनाएं जाहिर करने के लिए शब्द नहीं हैं। आदित्य ने कहा, मुझे अजित पवार के साथ पांच-छह साल काम करने का मौका मिला, पहले सरकार में और फिर विपक्ष में। विधायी मामलों पर उनकी मजबूत पकड़ और उनके खेली स्वभाव ने मेरे जैसे कई लोगों का दिल जीत लिया। विपक्ष में रहते हुए भी मैंने सार्वजनिक रूप से कई बार यह बात कही थी।

विमान दुर्घटना में अजित पवार की मृत्यु के मामले में जांच होगी - एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को विमान हादसे में अपने सहयोगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जिस विमान दुर्घटना में पवार की जान गई, उसकी जांच की जाएगी। शिंदे ने पत्रकारों से बातचीत में पवार के योगदान की सराहना की, जिन्होंने विभिन्न मंत्रिमंडलों में उनके सहयोगी के रूप में कार्य किया और 2022 से 2024 तक शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार में उपमुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने कहा, ''यह बहुत पीड़ादायक घटना है... महाराष्ट्र के लिए बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। विमान दुर्घटना की जांच की जाएगी। शिंदे ने कहा, ''यह क्षति केवल पवार परिवार की नहीं बल्कि पूरे राज्य की है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने बड़े भाई को खो दिया हो। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह पुणे जिले में विमान दुर्घटना में 66 वर्षीय पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई। शिंदे ने कहा कि पवार का मन शुद्ध था और वह साफगोई से बात रखने वाले निडर नेता थे जिनकी प्रशासन पर अच्छी पकड़ थी। उन्होंने याद किया कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान जब उन्होंने (2024 में) 'लाडकी बहिन योजना' शुरू करने का निर्णय लिया था तो कैसे तत्कालीन वित्त मंत्री पवार ने योजना के मद में वित्तीय व्यवस्था की थी, जिसके तहत राज्य की महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। शिंदे ने कहा, ''हमने (शिंदे, पवार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने) एक टीम के रूप में काम किया।